अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान: हर घर को 600 यूनिट मुफ्त बिजली, 90% बिल शून्य

फगवाड़ा (कपूरथला) | समर ब्यूरो

केजरीवाल ने कहा कि नए बुनियादी ढांचे का निर्माण, मौजूदा प्रणालियों को अपग्रेड करने और बिजली क्षेत्र में रखरखाव बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे वोल्टेज के उतार-चढ़ाव की समस्या खत्म हो जाएगी, खासकर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति में व्यापक सुधार होगा। आप के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि पंजाब में बिजली की कोई कमी नहीं है, लेकिन कई स्थानों पर सब-स्टेशन, बिजली लाइनें और अन्य बुनियादी ढांचा पुराना हो गया है, जिसके कारण बिजली आपूर्ति में समस्याएं आ रही हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बड़े शहरों में बिजली प्रणालियों को बेहतर बनाने के लिए विशेष परियोजनाएं भी लागू की गई हैं। उन्होंने कहा कि 13 नगर निगमों में लो टेंशन (एलटी) नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए परियोजना शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि बिजली के खंभों से अनावश्यक तारें हटाई जा रही हैं, नीचे लटक रही तारों को ऊंचा किया जा रहा है, पुरानी तारों को बदला जा रहा है और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खुले मीटर बॉक्स को सील किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अक्सर नीची या नंगी तारें हादसों का कारण बनती हैं, इसलिए यह परियोजना शुरू की गई। उन्होंने कहा कि इसे पहले पश्चिमी लुधियाना सब-डिवीजन में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया था और इसकी सफलता के बाद अब इसे अन्य शहरों में लागू किया जा रहा है। आप के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि यह पहल अब इन नगर निगमों के अधीन आने वाले सभी 87 सब-डिवीजनों में शुरू कर दी गई है और जून 2026 तक पूरी होने की उम्मीद है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए मोहाली में एक कॉल सेंटर स्थापित किया गया है और इसका हेल्पलाइन नंबर 1912 शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि कॉल सेंटर में 180 कर्मचारियों का स्टाफ है, जो दिन-रात लोगों की सहायता करता है। आप के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि पंजाब में पहली बार आम लोगों पर वित्तीय बोझ कम करने के लिए हर घर को 600 यूनिट मुफ्त बिजली देने की पहल शुरू की गई है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज पंजाब के 90 प्रतिशत घरों में बिजली का बिल शून्य है। उन्होंने कहा कि पहली बार किसी सरकार ने एक निजी पावर प्लांट खरीदा है और इस प्लांट का नाम तीसरे सिख गुरु श्री गुरु अमरदास जी के नाम पर रखा गया है। इस पवित्र अवसर पर सभी को बधाई देते हुए आप के राष्ट्रीय संयोजक ने उम्मीद जताई कि पंजाब हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छूता रहेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आप नेता अरविंद केजरीवाल की दूरदर्शी सोच ने पारंपरिक राजनीतिक दलों को अपने चुनावी घोषणा पत्र बदलने के लिए मजबूर किया है। उन्होंने कहा कि आप और इसके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के संयुक्त प्रयासों से शिक्षा, स्वास्थ्य

और बिजली के मुद्दे पार्टियों के राजनीतिक एजेंडे का केंद्र बिंदु बन गए हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले किसी भी राजनीतिक दल ने इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कभी प्राथमिकता नहीं दी थी, जो आम आदमी के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे इस तथ्य से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि बिजली अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है, इसलिए राज्य सरकार ने इस क्षेत्र के विस्तार के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। उन्होंने कहा कि यह बहुत गर्व और संतुष्टि की बात है कि राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से घरेलू, औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों को निर्बाध बिजली आपूर्ति मिल रही है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार के बड़े प्रयासों से 2015 से बंद पड़ी पछवाड़ा कोयला खदान से कोयले की आपूर्ति फिर से शुरू हो गई है, जिसके कारण अब राज्य के पास अतिरिक्त कोयला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की संपत्तियां केंद्र सरकार के मित्रों को मामूली कीमतों पर बेची जा रही हैं, जबकि दूसरी ओर राज्य ने गोइंदवाल पावर प्लांट को एक निजी कंपनी जीवीके पावर से खरीदकर इतिहास रचा है। उन्होंने कहा कि पहली बार यह उल्टा रुझान शुरू हुआ है कि किसी सरकार ने एक निजी पावर प्लांट खरीदा है, जबकि पहले की सरकारें अपनी संपत्तियों को कौड़ियों के भाव अपने चहेतों को बेच देती थी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार ने इस पावर प्लांट का नाम तीसरे सिख गुरु श्री गुरु अमरदास जी के नाम पर रखा है। उन्होंने कहा कि इस प्लांट से लोगों को बड़ी आर्थिक राहत मिली है। उन्होंने कहा कि बिजली क्षेत्र के इन सुधारों के साथ पंजाब देश के लिए एक प्रकाश स्तंभ बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और अकाली-भाजपा के कुप्रशासन के दौरान राज्य के बिजली क्षेत्र में कोई कदम नहीं उठाया गया। भगवंत सिंह मान ने कहा कि उनकी सरकार ने सत्ता संभालने के बाद बिजली क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। उन्होंने कहा कि नए सुधार राज्य में बिजली क्षेत्र को और मजबूत करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेरोजगारी कई सामाजिक समस्याओं की जड़ है, जिसके कारण राज्य सरकार इस समस्या को खत्म करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने बताया कि अब तक युवाओं को 55,000 से अधिक सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को नौकरियां पूरी योग्यता के आधार पर पारदर्शी तरीके से दी गई हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पिछली सरकारों द्वारा ड्रग माफिया को संरक्षण दिया जाता था, लेकिन उनकी सरकार ने नशे के खिलाफ युद्ध शुरू किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य से नशे की समस्या को खत्म करने के लिए उचित योजना बनाई गई है और अब नशे के खिलाफ आर-पार की जंग शुरू हो चुकी है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य सरकार पंजाब से हर तरह के अंधेरे को मिटाकर इसे रोशन करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार ने विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए पूरे राज्य में स्कूल ऑफ एमिनेंस स्थापित किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूल ऑफ एमिनेंस और अन्य सरकारी स्कूलों के 265 विद्यार्थी जे.ई.ई. मेन्स परीक्षा में योग्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि 44 विद्यार्थियों ने जे.ई.ई. एडवांस्ड पास किया है और 848 विद्यार्थियों ने नीट में योग्यता प्राप्त की है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में 881 आम आदमी क्लीनिक खोले गए हैं और इन क्लीनिकों की संख्या जल्द ही 1,000 को पार कर जाएगी। उन्होंने कहा कि अब तक इन क्लीनिकों में 1.75 करोड़ लोगों को मुफ्त दवाइयां दी गई हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस तरह के आयोजन पिछली सरकारों के दौरान कभी नहीं होते थे क्योंकि राज्य सरकार लोगों को अंधेरे में रखना चाहती थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने अपने कार्यकाल के पिछले साढ़े तीन वर्षों में पिछली सरकारों द्वारा पिछले 75 वर्षों में पैदा की गई गंदगी को साफ कर दिया है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि जिन अमीर और रसूख वाले नेताओं ने लोगों के अधिकारों को छीना या उनकी जिंदगियों को बर्बाद करने के लिए सत्ता का दुरुपयोग किया, उन्हें किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा, लोकसभा सांसद डॉ. राज कुमार चब्बेवाल, राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल और अन्य भी मौजूद थे।

पढ़ें पेज 1 पर-

पुलिस ने 5.6 किलोग्राम हेरोइन, 29 लाख रुपये की ड्रग मनी सहित 89 तस्करों को किया गिरफ्तार

चंडीगढ़ | समर ब्यूरो

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा राज्य से नशे के खात्मे के लिए शुरू की गई मुहिम 'युद्ध नशों विरूद्ध' के 221वें दिन पंजाब पुलिस ने बुधवार को राज्यभर में 381 स्थानों पर छापेमारी करते हुए 89 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया और 56 एफआईआर दर्ज कीं। इसके साथ ही, 221 दिनों में अब तक गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 32,324 हो गई है। छापेमारी के दौरान गिरफ्तार तस्करों के कब्जे से 5.6 किलोग्राम हेरोइन, 1 किलोग्राम अफीम, 484 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 29.22 लाख रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई। यह उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस

कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को पंजाब को नशा-मुक्त राज्य बनाने के निर्देश दिए हैं।

पंजाब सरकार ने नशे के खिलाफ चल रही जंग की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कैबिनेट उप-समिति का गठन भी किया है। 72 गजटेड अधिकारियों की निगरानी में 1000 से अधिक पुलिसकर्मियों वाली 120 से अधिक पुलिस टीमों ने राज्यभर में 381 स्थानों पर छापेमारी की। इन टीमों ने पूरे दिन चले इस अभियान के दौरान 420 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच भी की। राज्य सरकार ने नशे के उन्मूलन के लिए तीन-स्तरीय रणनीति - प्रवर्तन, नशा छुड़ाना और रोकथाम लागू की है। इसी के तहत पंजाब पुलिस ने आज 20 व्यक्तियों को नशा छुड़ाने और पुनर्वास इलाज करवाने के लिए राजी किया है।

राष्ट्रीय पिछड़ी श्रेणियां आयोग 14 अक्टूबर को चंडीगढ़ में करेगा जनसुनवाई

चंडीगढ़ | समर ब्यूरो

एक सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी दी कि राष्ट्रीय पिछड़ी श्रेणियां आयोग (एन.सी.बी.सी.), नई दिल्ली द्वारा 14 अक्टूबर, 2025 को दोपहर 2:00 बजे यू.टी. गेस्ट हाउस, चंडीगढ़ में एक जनसुनवाई आयोजित की जाएगी। इस जनसुनवाई का उद्देश्य पंजाब की विभिन्न जातियों को भारत सरकार की केंद्रीय ओ.बी.सी. सूची में शामिल करने से संबंधित मांगों पर विचार करना है। प्रवक्ता ने बताया कि यह जनसुनवाई पहले 9 अक्टूबर को निर्धारित की गई थी, लेकिन अब इसकी तिथि में बदलाव कर इसे 14 अक्टूबर कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस जनसुनवाई का मुख्य उद्देश्य संबंधित जातियों के प्रतिनिधियों को आयोग के समक्ष अपने विचार, तथ्य और मांगें सीधे तौर पर प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करना है। राज्य सरकार ने संबंधित जाति समूहों और उनके प्रतिनिधियों से इस जनसुनवाई में सक्रिय रूप से भाग लेने और अपने सुझाव आयोग के साथ साझा करने की अपील की है।

राष्ट्रीय पिछड़ी श्रेणियां आयोग 14 अक्टूबर को चंडीगढ़ में करेगा जनसुनवाई

चंडीगढ़ | समर ब्यूरो

पंजाब सरकार ने शुरू किया अब तक का सबसे बड़ा औद्योगिक बुनियादी ढांचा मिशन, आर्थिक विकास के लिए बन रहा है सुगम मार्ग चंडीगढ़, 8 अक्टूबरः पंजाब के औद्योगिक विकास को नई गति देने के लिए राज्य सरकार ने एक विशाल बहु-करोड़ रुपये का बुनियादी ढांचा मिशन शुरू किया है। यह महत्वाकांक्षी योजना राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों का स्वरूप बदलने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिससे नए निवेशकों और स्थानीय कारोबारों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार होगा। विस्तृत सुधारों की घोषणा करते हुए उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री संजीव अरोड़ा ने उत्साह व्यक्त करते हुए कहा कि पंजाब के औद्योगिक क्षेत्र का पुनरुत्थान शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा, "हम उद्योग जगत के नेताओं की आवाज़ को स्पष्ट रूप से सुन रहे हैं और श्री अरविंद केजरीवाल के मार्गदर्शन तथा मुख्यमंत्री भगवंत मान के दृढ़ समर्थन में हम निर्णायक ढंग से कार्य कर रहे हैं। हम ऐसी मजबूत नींव रख रहे हैं, जिससे हमारे उद्योग कमजोर बुनियादी ढांचे की बाधाओं को पार कर प्रगति कर सकें।" यह कदम उच्च-स्तरीय बैठकों की एक श्रृंखला के बाद उठाया गया, जिनमें उद्योग जगत के प्रतिनिधियों

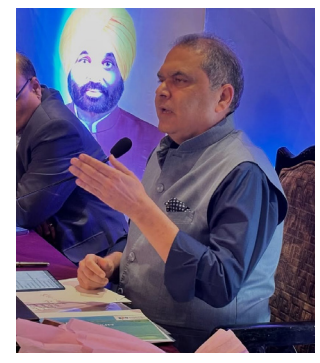

ने बुनियादी सुविधाओं में भारी कमी की ओर ध्यान दिलाया। इसके जवाब में पंजाब विकास आयोग (पी डी सी) ने तुरंत राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों में टीमें तैनात कीं। औद्योगिक संगठनों और स्थानीय प्रशासन के साथ ज़मीनी स्तर पर व्यापक विचार-विमर्श के बाद एक विस्तृत और चरणबद्ध उन्नयन योजना तैयार की गई। मंत्री ने कहा, "हमने अपने वादों को अमल में उतारना शुरू कर दिया है। टेंडर प्रक्रिया अब लाइव है, जो इस परिवर्तनकारी यात्रा की शुरुआत का संकेत है।" अब पूरे राज्य में विकास की एक नई लहर शुरू होने जा रही है। पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ एंड एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन (पी एस आई ई सी) 97.54 करोड़ रुपये के निवेश से 26 प्रमुख औद्योगिक फोकल पॉइंट्स के पुनरोद्धार का कार्य प्रारंभ कर रहा है। इस फंडिंग के तहत लुधियाना, मोहाली और अन्य जिलों में 32.76 करोड़ रुपये की लागत से मजबूत सड़कों और स्पष्ट संकेतक; 27.61 करोड़ रुपये के आधुनिक सीवरेज और एसटीपी; सभी पॉइंट्स के लिए सुदृढ़ जल आपूर्ति नेटवर्क; स्ट्रीट लाइटिंग और बेहतर नागरिक सुविधाओं का विकास किया जाएगा। इसके साथ ही, स्थानीय निकाय विभाग भी 134.44 करोड़ रुपये की परियोजना के तहत लुधियाना और खन्ना के 26 फोकल पॉइंट्स और 7 औद्योगिक जोनों में व्यापक परिवर्तन ला रहा है। यह उन्नयन विश्व-स्तरीय सड़कों और फुटपाथों, स्वच्छ पर्यावरण हेतु हरियाली, सीवरेज और जल सुविधाओं में सुधार, आधुनिक लाइटिंग की स्थापना तथा सीसीटीवी सुरक्षा से युक्त जिम और कम्युनिटी सेंटर जैसी नई सामुदायिक सुविधाओं की स्थापना करेगा। श्री अरोड़ा ने कहा, "हमारी समय-सीमा स्पष्ट है। मार्च 2026 तक पंजाब के औद्योगिक परिदृश्य की तस्वीर बदल जाएगी। हम तेज़ी से अमल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और हर कदम पर उद्योग जगत के फीडबैक के प्रति जवाबदेह रहेंगे। हमारा लक्ष्य सरल लेकिन सशक्त है — निर्बाध कार्य संचालन सुनिश्चित करना, लॉजिस्टिक लागत को घटाना और दुनिया को यह स्पष्ट संदेश देना कि पंजाब व्यापार के लिए सभी हेतु पूरी तरह तैयार है।"

भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाने वाली अवैध और आपत्तिजनक सामग्री संबंधी प्राप्त शिकायतों के बाद पंजाब में कई एफआईआर दर्ज

चंडीगढ़| भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाने वाली अवैध और आपत्तिजनक सोशल मीडिया सामग्री पर सख्त कार्रवाई करते हुए, पंजाब पुलिस ने आज राज्य के विभिन्न जिलों में सौ से अधिक सोशल मीडिया हैंडल्स के खिलाफ प्राप्त शिकायतों के आधार पर कई एफआईआर दर्ज की हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि सोशल मीडिया पर उच्च संवैधानिक अथॉरिटी पर हमले, जाति आधारित अपमान और भड़काऊ सामग्री, तथा जातीय और साम्प्रदायिक भावनाओं को अनुचित ढंग से प्रस्तुत कर शांति और सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने की प्रत्यक्ष कोशिश से जुड़ी सामग्री को फलैग किया गया है और कानून के अनुसार एफआईआर दर्ज की गई हैं। उन्होंने कहा कि इन पोस्टों और वीडियोज़ में जातिवाद और नफरत भरी सामग्री शामिल है, जिसका उद्देश्य सामाजिक फूट डालना, सार्वजनिक व्यवस्था भंग करना और न्यायिक संस्थानों की गरिमा को ठेस पहुँचाना है। प्रवक्ता ने आगे बताया कि इस सोशल मीडिया सामग्री में भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश की साख को ठेस पहुँचाने वाली अवैध और आपत्तिजनक बातें शामिल हैं। प्रवक्ता ने कहा कि गंभीर अपराधों से संबंधित प्राप्त जानकारी के आधार पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(आर), 3(1)(एस) और 3(1)(यू) तथा भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 196, 352, 353(1), 353(2) और 61 के अंतर्गत विभिन्न थानों में एफआईआर दर्ज की गई हैं। उन्होंने कहा कि कानून के अनुसार इन एफआईआर की आगामी जांच की जा रही है।

प्रशासनिक विभाग प्रस्तावों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में संबंधित यूनियन नेताओं को शामिल करें : हरपाल सिंह चीमा

चंडीगढ़ |समर ब्यूरो

पारदर्शिता और आपसी सहमति सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पंजाब के वित्त मंत्री और कर्मचारियों के मसलों के समाधान के लिए गठित कैबिनेट सब-कमेटी के चेयरमैन एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज प्रशासनिक विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि कर्मचारियों की मांगों और मसलों से संबंधित प्रस्तावों को वित्त विभाग, परसोनल विभाग या कैबिनेट सब-कमेटी को मंजूरी के लिए भेजने से पहले उन्हें अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में संबंधित यूनियन नेताओं को भी शामिल किया जाए। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने ये निर्देश ठेका मुलाजम संघर्ष मोर्चा, मुलाजम ते पेंशनर्स साझा मोर्चा, पंजाब राज वेटरनरी इंस्पेक्टर्स एसोसिएशन और होम गार्ड वेलफेयर एसोसिएशन (सेवानिवृत्त) के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा के दौरान दिए। उन्होंने कहा, ''यूनियन नेताओं से

परामर्श का यह कदम अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि अंतिम प्रस्ताव जमीनी हकीकत को सही ढंग से दर्शाते हुए कर्मचारियों द्वारा उठाए गए मुद्दों का उचित समाधान करें, जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता या शिकायत की कोई गुंजाइश न रहे।'' सिविल सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में इन चार कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशनों के साथ हुई सार्थक बैठकों की इस श्रृंखला के दौरान, वित्त मंत्री ने यूनियन नेताओं द्वारा प्रस्तुत की गई चिंताओं और मांगों को सहानुभूति के साथ सुना। इस दौरान संबंधित प्रशासनिक विभागों के अधिकारियों ने वित्त मंत्री को अवगत कराया कि अधिकांश जायज मांगों पर पहले से ही विचार किया जा रहा है और उनका समाधान प्रक्रिया में है। इस पर यूनियनों के प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्री का उनके सहानुभूतिपूर्ण और विस्तार से सुनवाई करने के लिए धन्यवाद प्रकट किया। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पुनः दोहराया कि कैबिनेट सब-कमेटी सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को स्पष्ट और कार्यान्वयन योग्य सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए प्रतिबद्ध है। बैठक के दौरान ठेका मुलाजम संघर्ष मोर्चा की ओर से वरिंदर सिंह मोमी, बलिहार सिंह, जगरूप सिंह, हरजीत सिंह, गगनदीप सिंह, जगसीर सिंह भंगू और जसवीर सिंह; मुलाजम ते पेंशनर्स साझा मोर्चा की ओर से सतीश राणा, धनवंत सिंह, करम सिंह धनोआ, सुखदेव सिंह सैणी और बॉबिंदर सिंह; पंजाब राज वेटरनरी इंस्पेक्टर्स एसोसिएशन की ओर से गुरदीप सिंह बासी, विपिन कुमार गोयल, गुरदीप सिंह शरना और परमजीत सिंह सोही; तथा होम गार्ड वेलफेयर एसोसिएशन (सेवानिवृत्त) की ओर से गुरदीप सिंह, भूपिंदर सिंह, सूरज प्रकाश और दरबारा सिंह ने अपने विचार प्रस्तुत किए।

बाजवा ने केंद्र से सहायता मांगने के लिए ज्ञापन तैयार करने में आप की उदासीनता के लिए निशाना साधा

चंडीगढ़|पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता ने बुधवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार पर कड़ी फटकार लगाते हुए उस पर पंजाब में बाढ़ पीड़ितों की दुर्दशा के लिए घोर अक्षमता और संवेदनहीन अवहेलना का आरोप लगाया। बाजवा ने तबाह राज्य के लिए केंद्र सरकार से आवश्यक सहायता मांगने के लिए आवश्यक ज्ञापन को अंतिम रूप देने में भी विफल रहने के लिए आप सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय पहले ही पंजाब सरकार को नुकसान का मूल हिसाब देने में पूरी तरह से असमर्थता के लिए फटकार लगा चुका है। उन्होंने हाल ही में एक समाचार रिपोर्ट की ओर इशारा किया, जिसमें खुलासा किया गया था कि नुकसान के अनुमानों को समेकित करने के लिए सोमवार को आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक अनिर्णायक रूप से समाप्त हो गई, जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत आंकड़े अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम को किए गए 13,832 करोड़ रुपये के नुकसान के पहले के दावे के साथ मेल खाने में विफल रहे। बाजवा ने कहा, 'यह कुप्रबंधन नहीं है, यह जानबूझकर कर्तव्य की अवहेलना है। बाजवा ने केंद्र सरकार से राहत मांगने की अपनी बुनियादी संवैधानिक जिम्मेदारी को पूरा करने के बजाय 'मिशन चारदी काला' और रंगला पंजाब फंड शुरू करने के लिए आम आदमी पार्टी की कड़ी निंदा की।